



# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## असाधारण भाग सात

वर्ष ६, अंक ३]

मंगळवार, मे ६, २०१४/वैशाख १६, शके १९३६

[पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १६

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

ग्राम विकास तथा जल संरक्षण विभाग

बांधकाम भवन, २५, मर्जबान पथ, फोर्ट,  
मुंबई ४०० ००१, दिनांकित ५ अप्रैल, २०१४ ।

**MAHARASHTRA ORDINANCE No. IX OF 2014.**

**AN ORDINANCE**

*further to amend the Maharashtra Village Panchayats Act.*

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ सन् २०१४ ।

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में अधिकतर संशोधन संबंधी अध्यादेश ।

सन् २०१४ का महा. २०१४ को प्रख्यापित किया था ;  
अध्या.  
क्र. २ ।

और क्योंकि २४ फरवरी, २०१४ को राज्य विधानमंडल के पुनःसमवेत होने पर उक्त अध्यादेश राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलने के लिये, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (संशोधन) विधेयक, २०१४ (सन् २०१४ का विधानपरिषद विधेयक क्रमांक १) २८ फरवरी, २०१४ को महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित किया गया था और महाराष्ट्र विधानसभा को पारेषित किया गया था ;

(१)

**और क्योंकि** उसके पश्चात्, महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र २८ फरवरी, २०१४ को सत्रावसित होने के कारण उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया जा सका था ;

**और क्योंकि** भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३(२)(क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश अर्थात् ६ अप्रैल, २०१४ के पश्चात् राज्य विधानमंडल के पुनःसमवेत होने से छह सप्ताह के अवसान पर प्रवृत्त होने से परिवर्तित हो जायेगा ;

**और क्योंकि** राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ;

**अब, इसलिए,** भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खंड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्वारा निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण । **१.** (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (संशोधन और जारी रहना) अध्यादेश, २०१४ कहलाए ।

(२) यह ३० जनवरी २०१४ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

सन् १९५९ का ३ की धारा ५४-१क की निविष्टि । **२.** महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम (जिसे इसमें आगे “मूल अधिनियम” कहा गया है), के अध्याय तीन-क की धारा ५४क के पूर्व, निम्न धाराएँ, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९५९ का ३ ।

ग्राम और ग्राम सभा से संबंधित विशेष उपबंध । **“५४-१क.** इस अधिनियम की धारा ४, ५ या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अनुसूचित क्षेत्रों में,—

(क) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए ग्राम साधारणतः समुदाय से मिलकर आवास या आवासों का समूह या खेड़ा या खेड़ो का समूह होगा और परंपराओं और प्रथाओं के अनुसार उसके कामकाज का प्रबंध जैसा कि विहितरीत्या घोषित किया जाएगा ;

(ख) खण्ड (क) के अधीन इस प्रकार घोषित प्रत्येक ग्राम की एक **ग्राम सभा** होगी ; ग्राम स्तर पर पंचायत के निर्वाचक नामावली में जिनके नाम शामिल है और पंचायत एक या एक से अधिक ऐसे ग्राम से मिलकर हो होगी ।”।

सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. २ का निरसन और व्यावृत्ति । **३.** (१) महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ एतद्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. २।  
(२) ऐसे प्रत्याहरण के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित (जारी किसी अधिसूचना समेत) मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत किसी बात या की गई कोई कार्यवाही, इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिती, जारी की गई समझी जायेगी।

**वक्तव्य।**

संसदने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग नौ के उपबंधों का विस्तार करने की दृष्टि से, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, १९६६ (सन् १९६६ का ४०) (जिसे संक्षिप्त में “**पेसा**” निर्दिष्ट किया गया है) के उपबंधों को अधिनियमित किया है। संसद के उक्त अधिनियम के अनुसरण में, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम (सन् १९५९ का ३) अनुसूचित क्षेत्रों में **ग्राम सभाओं** और पंचायतों के लिए अन्तर्विष्ट विशेष उपबंध अलग अध्याय तीन-क को निविष्ट करके सन् २००३ का महा. २७ द्वारा संशोधित किया गया है।

२. **पेसा** के अनुसरण में, यह सुनिश्चित करना इष्टकर समझा गया है कि समुदाय से मिलकर किसी आवास या आवासों का समूह या खेड़ा या खेड़ों का समूह से होगा और परम्पराओं और प्रथाओं के अनुसार उसके कामकाज का प्रबन्ध ग्राम द्वारा घोषित किया जा सकेगा और ऐसी घोषणा पर प्रत्येक ऐसे ग्राम में एक **ग्राम सभा** होगी। इससे पंचायत राज प्रणाली में अनुसूचित क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण गहरा होगा और निवासियों की बेहतर भाग लेने की अगुआई होगी, जो विद्यमानतः उनके निवास बहुधा सुदूर और बिखरे स्वरूप के कारण सिमित है। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे ग्रामों की **ग्राम सभा पेसा** के अधीन ऐसी **ग्राम सभा** पर प्रदत्त अधिकारों के उपयोग द्वारा विकास में भाग ले सकेगी। इस प्रयोजन के लिए, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम (सन् १९५९ का ३) में तत्काल संशोधन करना इष्टकर समझा गया है।

३. क्योंकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था, और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम (सन् १९५९ का ३) में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (सन् २०१४ का महा. अध्यादेश क्र. २) ३० जनवरी २०१४ को प्रख्यापित किया था।

४. तत्पश्चात् २४ फरवरी २०१४ को राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलने के लिए, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (संशोधन) विधेयक, २०१४ (सन २०१४ का विधान परिषद विधेयक क्र. १) २८ फरवरी २०१४ को महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित किया गया था और महाराष्ट्र विधानसभा को पारेषित किया गया था। तथापि तत्पश्चात् महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र २८ फरवरी २०१४ को सत्रावसित होने के कारण उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया जा सका था।

५. संविधान के अनुच्छेद २१३(२)(क) के उपबंधों के प्रवर्तन द्वारा उक्त अध्यादेश अर्थात् ६ अप्रैल, २०१४ के पश्चात् राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने से छह सप्ताह के अवसान से प्रवृत्त होने से परिविरत होगा।

६. क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. २) के उपबंध जारी रखने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था।

मुंबई,  
दिनांकित ४ अप्रैल २०१४।

के. शंकरनारायणन्,  
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

एस. एस. संधू,  
शासन के प्रधान सचिव।

(यथार्थ अनुवाद)

श्रीमती ललिता शि. देठे,  
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।